

[Secretary]

8. The Delhi Tenants (Temporary Protection), Bill, 1956,
9. The Delhi (Control of Building Operations) Continuance Bill, 1956,
10. The Delivery of Books (Public Libraries) Amendment Bill, 1956.

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary of Rajya Sabha, of the following 17 Bills passed by the Houses of Parliament during the last session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 22nd December, 1956:

1. The Manipur (Village Authorities in Hill Areas) Bill, 1956,
2. The State Bank of Hyderabad Bill, 1956,
3. The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Bill, 1956.
4. The Road Transport Corporations (Amendment) Bill, 1956,
5. The Representation of the People (Miscellaneous Provisions) Bill, 1956,
6. The Standards of Weights and Measures Bill, 1956,
7. The Administration of Evacuee Property (Amendment) Bill, 1956,
8. The Territorial Army (Amendment) Bill, 1956,
9. The Young Persons (Harmful Publications) Bill, 1956,
10. The Employees' Provident Funds (Amendment) Bill, 1956,
11. The Banking Companies (Amendment) Bill, 1956,
12. The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1956,
13. The Electricity (Supply) Amendment Bill, 1956,
14. The Indian Medical Council Bill, 1956,
15. The Territorial Councils Bill, 1956,

16. The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Bill, 1956, and

17. The Women's and Children's Institutions (Licensing) Bill, 1956.

#### PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 18th March 1957.

#### President's Address

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, प्राज्ञ मैं पूरे एक वर्ष के बाद आप के सामने अभिभाषण कर रहा हूँ। यह वर्ष हमारे देश के लिये और विश्व के लिये महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहा है। हम ऐसे समय एकत्र हुये हैं जब कि देश भर में ग्राम चुनाव चल रहे हैं और इनके परिणाम-स्वरूप नई संसद् की स्थापना होने जा रही है। इस संसद् के सम्मुख कुछ कहने का मेरे लिये यह अन्तिम अवसर है। अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में आप में से कुछ नई संसद् में भी आयेंगे और संभवतः कुछ सदस्यगण नई संसद् में नहीं आयेंगे। आप का कार्यक्षेत्र कहीं भी हो, मुझे इस में संदेह नहीं कि जो कुछ भी आप करेंगे वह इस देश के निर्माण संबंधी महान कार्य के हित में होगा। मैं आप के कार्य में सफलता और आप की सम्पन्नता की कामना करता हूँ।

पिछली बार जब मैंने आप के सामने अभिभाषण दिया था, तब से संसार ने, विशेष कर मध्यपूर्व ने, तनाव की स्थिति का सामना किया है और एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जिस का अन्तिम रूप मिस्र पर आक्रमण हुआ। संयुक्तराष्ट्र के हस्तक्षेप और संसार के जनमत के फलस्वरूप आक्रमणकारी सेनाओं को मिस्र से हटा लिया गया, किन्तु इस संघर्ष से मिस्र को भारी क्षति ही नहीं उठानी पड़ी बल्कि ऐसे समय जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा था तनाव में बुद्धि हुई। इन

परिस्थितियों के कारण बहुत सी समस्याओं पैदा हो गई हैं जिन्हें अब सुलझाना होगा। इन समस्याओं से हमारा भी गहरा संबंध है क्योंकि विश्व-शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी दिलचस्पी है और हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिये इन कठिनाइयों को सुलझाने में हम नै योगदान देने की चेष्टा की। इस प्रकार हमारे देश ने अपने ऊपर भारी दायित्व लिये हैं जिन में संयुक्तराष्ट्र आपत्कालिक सेना में सम्मिलित होना भी शामिल है। यह सेना संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के निर्णय के अनुसार और धारुमणकारी सेनाओं के वापसी-संबंधी प्रस्ताव के अन्तर्गत संगठित की गई थी।

मध्य यूरोप में हंगरी में घटने वाली घटनाओं से हमें बहुत खबराहट हुई और दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हम नै विदेशी सेनाओं की वापसी के लिये और राष्ट्रीय आंदोलनों के दमन के लिये उन के प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके साथ ही विभिन्न भवसरों पर इस समस्या का हल ढूढने में हम नै भरसक सहायता करने की चेष्टा की और हंगरी के लोगों की सामाजिक सहायता के रूप में उन के प्रति सहानुभूति प्रकट की।

विश्व-शांति और सहयोग की संभावनाओं पर मध्यपूर्व की स्थिति की परछाई पड़ी है। उच्च यातायात के लिये स्वेज नहर का खुलना बाकी रहता है। इस क्षेत्र में सैनिक संघियों की नीति नै राष्ट्रों को आपस में बांट दिया है और एशिया में अधिकधिक युद्ध सामग्री जुटाई जाने लगी है। फिर भी यह बेस कर कि इस क्षेत्र में संघर्ष का और अधिक विस्तार नहीं हुआ हमें संतुष्ट होना चाहिये।

मूलपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश, गोल्ड कोस्ट और इस के साथ अंग्रेजी शासन के अधीन टोगोलैंड का प्रदेश अब घाना नामक स्वतंत्र और सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में उचित हुआ है, इस बात से भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत खुशी हुई है।

हम संयुक्तराष्ट्र में सूडान, मोरक्को, ट्यूनीसिया, जापान तथा घाना के प्रवेश का स्वागत करते हैं। मंगोलिया के बराबर बाहर रहने और चीन के अधिकृत प्रतिनिधियों को संयुक्तराष्ट्र में स्थान न दिये जाने के कारण हमें शोभ होता है और इस स्थिति का प्रतिकार करने में हम बराबर प्रयत्नशील हैं।

हम आशा करते हैं कि मलाया क्षेत्र ही एक स्वतंत्र देश बन जायगा और ऐसा होने से उपनिवेशवाद का प्रभाव और कम हो जायगा और एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता की सीमायें विस्तृत हो सकेंगी।

संयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा के ११ वें सत्र में मध्यपूर्व, अल्जीरिया और साइप्रस-संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले विवादों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावोत्पादक और उपयोगी योगदान दिया है और इन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूढने और कार्यप्रणाली तय करने में सहायता दी है। निःशस्त्रीकरण का कार्य प्रागे नहीं बढ़ा है किन्तु संयुक्तराष्ट्र ने एकमत से अपने प्रयत्न जारी रखने और भारत के सुझाव समेत सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय किया है। भारत सरकार को खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सहायक हो सकी।

हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी के प्रारम्भिक आयोग का सदस्य था। इसलिये हमें इस बात का संतोष है कि इस एजेंसी की अब स्थापना हो गई है। हमारी यह कामना तथा आशा है कि अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में होगा और विध्वंसक कार्यों में इस का प्रयोग बन्द हो सकेगा।

अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की यात्रा का मुझे सुख और सीमाध्य प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति नै महामहिम नेपाल नरेश महेन्द्र की बिक्रम शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में नेपाल

## [ राष्ट्रपति ]

सरकार तथा वहाँ की जनता के प्रयत्नों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमें खुशी है कि हम उन की पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने में टेकनिकल तथा आर्थिक सहायता दे सकें।

भारत में बुद्ध जयन्ती-संबंधी समारोहों के कारण हमें अपने देश में दलाई लामा तथा पंचन लामा और संसार के विभिन्न भागों के बौद्ध नेताओं के स्वागत का सुभवसर मिला। इस समारोह ने हमें और संसार को भगवान बुद्ध के शांति तथा कल्याण के संदेश का फिर से स्मरण कराया। आज विश्व को इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है।

अपने देश में अनेक सम्मानित प्रागान्तुकों का स्वागत करने और उनका परम्परागत आतिथ्य करने का भारत सरकार और इस देश के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे इन सम्मानित अतिथियों में महामहिम ईरान के शहनशाह तथा साम्राज्ञी, महामहिम इथोपिया के सम्राट, सीरिया के राष्ट्रपति, शुकी-अल-कुवतली, कम्बोडिया के राजकुमार परमश्रेष्ठ नरोदम सिंहनुक, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल और डेन्मार्क के प्रधान मंत्रीगण, जर्मनी के संघीय गणतंत्र के उपचांसलर, सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री, सूडान के उपप्रधान मंत्री और अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री शामिल हैं। १९५६ में संयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष, डा० जोड माजा और संयुक्तराष्ट्र के महामंत्री भी हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल थे। बर्मा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, डेन्मार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नौर्वे, पोलैंड, स्वीडन, सीरिया और यूगेंडा से संसदीय, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा सद्भावना-सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल भी हमारे देश में आये।

भारतीय उपराष्ट्रपति ने सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया,

बल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीकी संघ, इंडोनेशिया तथा जापान की यात्रा की और सभी देशों में उनका हार्दिक स्वागत हुआ।

राष्ट्रपति झाड़जनहावर के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से तथा अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री में विचार-विनिमय के फलस्वरूप हमारे दोनों देशों के बीच अधिक सद्भावना हुई तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण के समझने में सहायता मिली। मेरी सरकार को विश्वास है कि इस के द्वारा पारस्परिक सम्मान तथा सद्भावना के आधार पर दोनों देशों में अधिकाधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।

केनेडा के प्रधान मंत्री, श्री लुई सेंट लारां के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने केनेडा की यात्रा की। यह यात्रा केनेडा और हमारे देश के बीच सुखद सम्बन्धों को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे दोनों देशों में सदा निष्ठा के और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं।

मेरी सरकार को खेद है कि दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति की समस्या को सुलझाने और अफ्रीकियों तथा भारतीय वासियों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को दूर करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। मेरी सरकार के सुझाव पर संयुक्तराष्ट्र संघ ने एक बार फिर इस समस्या पर विचार किया। बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिये संयुक्तराष्ट्र ने सम्बद्ध सरकारों से फिर अपील की है। पहले की तरह भारत सरकार ने फिर स्वेच्छा से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मेरी सरकार को हार्दिक खेद है कि योधा अभी भी पुर्तगाली सरकार की धीपनिवेशिक चौकी के रूप में बना है और वहाँ प्रत्येक प्रकार की स्वाधीनता का दमन किया जा रहा

है और आर्थिक उन्नति आवश्यक है। मेरी सरकार की यह दृढ़ नीति है कि गोआ को औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिये और भारत की स्वाधीनता में साझेदार होना चाहिये।

मेरी सरकार को खेद है कि पाकिस्तान से इसके सम्बन्धों में बराबर कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान में भारत-विरोधी और जहाद के आंदोलनों में कुछ भी कमी नहीं आई। भारत सरकार और देश के लोगों का दृष्टिकोण यह है कि हम घृणा का उत्तर घृणा से नहीं देंगे, किन्तु अपने न्यायोचित हितों तथा देश की रक्षा करते हुये दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों की निकासी गत वर्ष बराबर होती रही और इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। कुल मिला कर पूर्वी पाकिस्तान से ४० लाख से ऊपर लोग भारत में आ चुके हैं और इन लोगों के आ जाने से हमारे देश पर, विशेष कर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, भारी बोझ पड़ा है।

पाकिस्तान सरकार के आवेदन पर संयुक्तराष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के मामले पर विचार किया गया। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट और निर्विवाद शब्दों में व्यक्त की गई है, अर्थात् अक्तूबर, १९४७ से जम्मू और काश्मीर राज्य भारतीय संघ के दूसरे राज्यों की तरह देश का एक वैधानिक भाग रहा है और अब भी है। काश्मीर में जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्तराष्ट्र द्वारा पास किये गये प्रस्तावों में निहित समझौतों की अवहेलना करके, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और भारतीय संघ के भूभाग पर अवैध रूप से अधिकार कर लेना है। सुरक्षा परिषद् में गत मास अपने तत्कालीन सभापति को भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करने के लिये इन देशों में भेजने का विवक्षय किया। अपनी साधारण नीति के

अनुसार भारत सरकार ने स्वीडन निवासी श्री यारिंग का, जिन के शीघ्र ही यहां भ्राने की आशा है, स्वागत तथा उनका प्रातिप्य-सत्कार करने की सहमति दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जिस में पहले सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, अब कम आशाजनक दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बराबर बने हैं, यद्यपि विश्व की स्थिति में बिगाड़ का पूर्व के देशों के शांतिपूर्ण सम्बन्धों, परस्पर सहयोग तथा आर्थिक विकास पर दूषित प्रभाव पड़ा है। शक्ति के संतुलन पर आधारित सैनिक गुटों की नीति के कारण विशेष रूप से एशिया में तनाव बढ़ा है। शस्त्रास्त्रों में वृद्धि हुई है और शीत-शुद्ध के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरी सरकार की बराबर यह दृढ़ धारणा है कि शांतिपूर्ण बातचीत और पारस्परिक समझौतों द्वारा ही विश्व की समस्याओं को ठीक और आशाजनक ढंग से सुलझाया जा सकता है।

गत वर्ष राज्यों के पुनर्गठन का कार्य समाप्त कर लिया गया और यह कार्य, जिस के कारण देश के कुछ भागों में दुर्भाग्यवश भावातिरेक के प्रदर्शन हुए, अब सम्पन्न हो चुका है। गत वर्ष ही पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सफलतापूर्वक समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इस योजना में खाद्यों के उत्पादन पर पहले की तरह जोर दिया गया है किन्तु इसके साथ ही देश के औद्योगिक विकास, विशेषकर बड़े उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का देहाती इलाकों में आश्चर्यजनक तेजी से विस्तार हुआ है। इन सेवाओं के अन्तर्गत अब दो लाख बीस हजार गांव और १२ करोड़ ६० लाख जनसंख्या प्राप्ती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में छोटे और बरेलू उद्योगों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

## [ राष्ट्रपति ]

सैनिक पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप तेल की आशाजनक खोज हुई है और राजस्थान तथा बिहार में यूरेनियम का पता लगा है। बोरियम और यूरेनियम की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण इन धातुओं के हमारे ज्ञात साधन दुगुने से भी अधिक हो गए हैं। हमारे अणुशक्ति विभाग ने भी प्रगति की है और भारत का पहला अणु रिएक्टर गत वर्ष चालू हो गया। सोवियत संघ से बाहर एशिया में स्थापित होने वाला यह पहला अणु रिएक्टर है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त होन वाला है। विगत वर्ष में कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने आई हैं। कुछ चीजों के भाव ऊँचे चढ़े हैं और विदेशी विनिमय के हमारे साधन संकुचित हो गए हैं। यह गति-विधि देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बढ़ते हुए उत्पादन की परिचायक है। देश में धन लगाने पर जोर और अधिक उप-भोग्यता पदार्थों की अधिक मांग त्वरित विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है और एक हद तक इस प्रकार का दबाव इस बात का द्योतक है कि विकास के हित में देश के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। किन्तु हमें सावधान रहना चाहिये कि यह दबाव बहुत अधिक न होने पावे। भावों के चढ़ाव को रोकने के लिये और विदेशी विनिमय के साधनों के ह्रास की रोकथाम के लिये सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ है।

इस दिशा में सरकार के सामने प्रमुख समस्या विदेशी विनिमय के साधनों की सुरक्षा तथा वृद्धि की है। जिस देश में मशीनें तैयार करने की काफी क्षमता न हो, उसे औद्योगीकरण के लिये आवश्यक रूप से विदेशी विनिमय अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। विदेशी विनिमय पूँजी में सहसा अधिक वृद्धि संभव नहीं, इसलिये देश के साधनों के विकास के हित में आरम्भ में विदेशीसहा-

यता आवश्यक होती है। फिर भी अधिक-धिक विदेशी विनिमय उपायित करना और आयात में मितव्ययता से काम लेना प्रत्येक देश के लिये अनिवार्य है। धमरीकी सरकार से हाल में ही जो समझौता हम ने किया है और जिस के अनुसार हमें विपुल मात्रा में गेहूँ, चावल और रूई उपार मिल सकेगा, उस से हमें चढ़ते हुए भावों को रोकने और अपनी योजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि विश्व बैंक सरीखी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से भी हमें काफी वित्तीय सहायता मिलेगी। फिर भी यह निर्विवाद है कि विकास के कार्यों के लिये आवश्यक साधनों को हमें अपने बल पर ही जुटाना होगा और इस के लिये उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्यों से हमें जनता को संगठित करना होगा।

दूसरी योजना में औद्योगीकरण और आर्थिक व्यवस्था के विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये खाद्य, कपड़ा और उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक कच्चे माल-सम्बन्धी आधारभूत पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस योजना में अधिक धन लगाने पर भी जोर दिया गया है और रोजगार के साधनों का विस्तार इस के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। रोजगार के बढ़ाने और धन लगाने से जो आयात होगा वह अधिकतर सुराक और कपड़े पर लम्बे होगी। इसलिये इन दोनों चीजों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही योजना को मुद्राबाहुल्य का संकट उपस्थित किए बिना, आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास के क्षेत्र में हमारे प्रयासों का प्रमुख आधार है। इस काम के लिये जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

१९५७-५८ वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आग्रह व्यय के अनुमानित आंकड़ों का प्रमुख रत्ने जायेंगे जिस के कि आग्रह

इस पर अपना मत दे कर आलोच्य वर्ष के एक मास के लिए खर्च करने की अनुमति दे सकें। इसके अतिरिक्त केरल राज्य के संबंध में भी इसी प्रकार के अंक भाष का अनुमोदन प्राप्त करने के हेतु आप के सामने रखे जायेंगे।

संसद् का यह सत्र स्वल्प होगा और इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार विवादास्पद विधान हाथ में नहीं लिया जाएगा। कुछ अध्यादेश जो विगत सत्र के बाद जारी किए गए थे संसद् के समझ रखे जायेंगे।

पांच वर्ष हुए इस महान देश के मत-दाताओं की प्रतिनिधि स्वरूप यह संसद् चुनी गई थी और इसने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिये और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापन के लिये यत्न किया है। इस यत्न का सुखद फल हुआ है जिसे हम देश में चारों ओर देखते हैं। जो सफलताएँ आपने इस अवधि में प्राप्त की हैं उन पर, संसद् के सदस्यगण, मैं आप को बधाई देना चाहता हूँ। परन्तु हम में से कोई भी निश्चिन्त हो कर बैठ नहीं सकता क्योंकि नवीन और सम्पन्न भारत के निर्माण की कहानी सदा घटित होती रहेगी जिस से इस देश की जनता को सुख प्राप्त होगा और विश्व शांति तथा सहयोग के पक्ष को बल मिलेगा।

मैं आशा करता हूँ कि भगवान् बुद्ध का सन्देश, जिन की जयन्ती हम ने हाल में ही मनाई थी, तथा हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा हमें सत्प्रेरणा देती रहेगी।

**The President:** Members of Parliament, I am addressing you today after a full year, a year which has witnessed significant happenings in the world and considerable developments in our own country. We are meeting at a time when general elections are being held all over the country, and a new Parliament is coming into being as a result of these elections. This is the last occasion when I am addressing this Parliament. Some of you will come back to represent your constituencies in the new Parliament and

some of you may not return. But I have no doubt that wherever your field of work may lie, it will be dedicated to the great task of building up this country of ours. I wish you success and good fortune in your field of activity.

Since I addressed you last, the world has seen a period of high tensions, particularly in the Middle East, and of conflict ending in the invasion of Egypt. The intervention of the United Nations and the impact of world opinion resulted in the withdrawal of the invading armies from Egypt; but the conflict has not only done great damage to Egypt but has added to the tensions which were showing signs of relaxation, and has left in its wake many problems to be resolved. Our country, which is deeply involved both on account of her concern for world peace and cooperation and her own interest, has sought to assist in resolving these difficulties. India has accepted greater burdens including participation in the United Nations Emergency Force constituted by the decision of the General Assembly of the United Nations which called for the withdrawal of the invading forces.

In Central Europe, the events in Hungary have disturbed us greatly and here, as elsewhere, we have stood for the withdrawal of foreign forces and against their use against peoples and national movements. At the same time, we have used our best efforts to assist in finding solutions to the problem at its various stages and extended our sympathy and our token of assistance to the people of Hungary.

The position in the Middle East casts its shadow over the prospects of cooperation and peace and the Suez Canal awaits opening for traffic. The policy of military pacts has divided the nations in this region and brought the apparatus of war more and more into Asia. We must, however, note with relief that the conflict in this region did not grow to greater dimensions.

Our Government and people rejoice in the fact that the former British colony of the Gold Coast, along with

[The President]

the former Trust Territory of Togoland under British administration, has now been constituted into the independent and sovereign State of Ghana and a full member of the Commonwealth of Nations.

We welcome the admission of Sudan, Morocco, Tunisia, Japan and Ghana to the United Nations. The continued exclusion of Mongolia and the denial to the rightful representatives of China of their place in the United Nations, cause us deep concern and we continue to devote our endeavours to remedy this situation.

We hope that Malaya will soon become a free and independent State and this will further limit the sphere of colonialism and extend the area of national freedom in Asia.

In the United Nations, the Indian Delegation, in the Eleventh Session of the General Assembly, has made effective and useful contributions in the prolonged debates on crucial issues in regard to the Middle East, Algeria and Cyprus, and contributed to peaceful solutions and procedures in respect of them. Disarmament has made no progress, but the United Nations unanimously resolved to continue its efforts to consider all proposals before it, including the proposals made by India. The Government of India are happy to have been able to assist in promoting this resolution.

Our country, which was a member of the Preparatory Commission of the International Atomic Energy Agency, can derive satisfaction that the Agency has now been established. May it fulfil the hopes that atomic energy will be harnessed for peaceful uses and also diverted from destructive purposes.

I had the happy privilege of visiting our near neighbour, Nepal; and the Vice President represented our country at the Coronation of His Majesty King Mahendra Bir Bikram Shah. The endeavours of the Nepal Government and people for economic and social development have our full sympathy, and we are happy that we

have been able to extend technical and economic assistance to them in the implementation of their Five Year Plan.

The Buddha Jayanti celebrations in India gave us the opportunity of welcoming in this country the Dalai Lama and the Panchen Lama, as well as leaders of Buddhism from different parts of the world. These celebrations reminded us and the world afresh of the great message of peace and compassion of the Buddha, which is so much needed in the world today.

We have been privileged to receive in our country many distinguished visitors to whom my Government and the people of India have extended their traditional hospitality. Among these eminent guests of ours have been Their Imperial Majesties the Shahenshah and the Empress of Iran, His Imperial Majesty the Emperor of Ethiopia, President Shukri El-Kuwatly of Syria, His Royal Highness Prince Norodom Sihanouk of Cambodia, Prime Ministers of Burma, Ceylon, Indonesia, China, Nepal and Denmark, the Vice Chancellor of the Federal Republic of Germany, the Deputy Prime Minister and Defence Minister of the Soviet Union, the Deputy Prime Minister of Sudan and the Foreign Ministers of the United States, France and the United Kingdom. The President of the United Nations General Assembly for 1956, Dr. Jose Maza, and the Secretary General of the United Nations were also among our distinguished visitors. Parliamentary, cultural, trade and other goodwill delegations from Burma, China, Czechoslovakia, Denmark, Germany, Indonesia, Japan, Norway, Poland, Sweden, Syria and Uganda have also visited our country.

The Vice President paid visits to the Soviet Union, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Rumania, Bulgaria, East Africa, the Central African Federation, Indonesia and Japan and received a very warm welcome everywhere.

My Prime Minister visited the United States at the invitation of

President Eisenhower. The visit and the talks between the President of the United States and my Prime Minister have assisted in the promotion of understanding between our two countries and greater appreciation of each other's point of view. My Government feel confident that it will lead to increasing co-operation in all fields on the basis of mutual respect and understanding.

My Prime Minister also visited Canada at the invitation of Mr. Louis St. Laurent, the Prime Minister of Canada. His visit has helped to further enrich the relations between Canada and our country, which have always been very friendly and close.

My Government regret that no progress has been made in regard to the solution of the problem of "apartheid" and discrimination against Africans and people of Indian origin in South Africa. This problem once again received the consideration of the United Nations at the instance of my Government. A further appeal to the Governments concerned to find a solution by negotiations has been made by the United Nations. The Government of India, as in the past, has readily subscribed to this resolution.

My Government deeply regret that Goa still continues to be an unhappy colonial outpost of the Portuguese Government, where every kind of liberty is suppressed and economic stagnation prevails. It is the firm policy of my Government that Goa should become free from colonial domination and should share in the freedom of the rest of India.

My Government regret that its relations with Pakistan continue to present difficulties and there has been no abatement in Pakistan of the campaigns of hatred and 'jehad'. The policy of the Government of India and the general approach of our people have been that we shall not respond to these with hatred, but shall continue our endeavours to promote friendly relations while defending our land and our legitimate interests. The exodus of people from East Pakistan to India continued throughout this past year

and assumed alarming proportions. Altogether, over four million people have come from East Pakistan to India, and these persons have cast a heavy burden on our country and, more especially, on the State of West Bengal.

The problem of Kashmir was considered by the Security Council of the United Nations once again, at the request of the Government of Pakistan. The Government of India's position has been stated in clear and unambiguous terms, that the Jammu and Kashmir State is and has been a constituent State of the Indian Union since October 1947, like other States which acceded to the Union. The present situation in Kashmir has arisen from aggression and on illegal occupation of Union territory by Pakistan in violation of international law and agreements and engagements reached in pursuance of United Nations resolutions. The Security Council has resolved last month to send its then President to Pakistan and India to confer with the two Governments. The Government of India, in accordance with its general policy, has agreed to receive and extend hospitality to Mr. Jarring of Sweden who is expected to arrive here soon.

The world situation as a whole, which was beginning to show some signs of improvement, gives us cause for less optimism at present. Our own country, however, continues to have friendly relations with all countries, but the deterioration in the world situation has adverse results on the development of peaceful relations and co-operation and economic development in our part of the world also. More particularly, the policy of military pacts based upon the balance of power, mutual suspicion and fear, has increased tensions in Asia and has led to the increase of armaments and extended the area of cold war. It continues to be the firm belief of my Government that only by a peaceful approach and agreed settlements can be found the right and hopeful way for solutions of the world's problems.

## [The President]

During the past year, the reorganisation of the States was completed, and this great task which had unfortunately roused much passion in some parts of the country, was accomplished. During the past year also, the first Five Year Plan was successfully completed and the second Five Year Plan begun. This Plan, while continuing to lay stress on greater food production, emphasises the need for industrial development, more especially in regard to heavy industry. The Community Projects and the National Extension Service have been extended with phenomenal rapidity over our rural areas and now cover two hundred and twenty thousand villages and a rural population of one hundred and twenty-nine millions. In the community development scheme, special stress is being laid on the development of small scale and cottage industries.

Mineral surveys have yielded promising discoveries of oil, and many new deposits of uranium ore have been located in Rajasthan and Bihar. The finds of thorium and uranium minerals in large quantities have more than doubled our known reserves of these minerals. The work of our Atomic Energy Department has made great progress, and India's first atomic reactor began operations last year. This is the first reactor to go into operation in Asia, outside the Soviet Union.

We are about to complete the first year of the Second Five Year Plan. Certain stresses and strains have emerged in the course of this year. Prices of certain commodities have risen and there has been a substantial draught on the foreign exchange resources of the country. These factors reflect the growing tempo of development in the country, in the public as well as in the private sectors. The growth of internal demand for consumption and for investment is a concomitant of rapid development and, up to a point, the emergence of such pressures is a sign that the resources of the country are being stretched in the interests of development. It is

however, essential to ensure that these pressures do not go too far. Government are determined to take appropriate measures to restrain the rise in prices and to reduce the drain on foreign exchange resources.

The major problem before the country in this context is that of conserving and increasing its foreign exchange resources. For a country which starts with insufficient facilities for producing machinery and equipment, a plan of industrialisation necessarily involves heavy foreign exchange expenditure. Since it is difficult in the short run to enlarge foreign exchange earnings substantially, developing economies require an inflow of external resources in the initial stages. It is, however, incumbent on the country concerned to earn the maximum foreign exchange it can and to exercise the utmost economy in the matter of imports. The recent agreement with the United States Government, under which large quantities of wheat, rice and cotton will be available to us on credit terms, will help in checking the rise in prices and will contribute to the furtherance of the Plan. Considerable external finance will, we expect, be forthcoming, from international agencies like the World Bank and from friendly countries. Nevertheless, the bulk of the resources required for development must come from within the country and the community has to be organised for a big production effort to make this possible.

The Second Plan gives high priority to industrialisation and to the diversification of the economic structure. This, in turn, requires a substantial increase in the production of basic necessities like food and cloth and of raw materials required for the developing industries. The Plan calls for more investment, and one of its principal aims is to enlarge employment opportunities. New incomes created by investment and employment are mostly spent on food and cloth and it is only if their supplies can be increased rapidly that the Plan can go forward without creating an

inflationary situation. An increase in agricultural production thus constitutes the pivot of developmental effort and for this we need the fullest co-operation of every section of the community.

A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1957-58 will be laid before you for the purpose of passing votes on account authorising expenditure for a part of that year. In addition, a similar statement in respect of the Kerala State will also be laid before you for passing a vote on account for a part of the year for that State.

This session of Parliament will be a brief one and no major or controversial legislation will be taken up during this session. Some Ordinances which have been promulgated since the last session will be placed before Parliament.

Five years ago this Parliament came into existence representing the vast electorate of this great country, and it has laboured for the well-being and advancement of India and for peace and co-operation in the world. These labours have produced substantial results which we see all round us in the country, and I wish to offer you, Members of Parliament, my congratulations on the great tasks that have been accomplished. But there is no resting place for any of us and the great story of the building up of a new and prosperous India will continue to unfold itself, bringing happiness to all our people and serving the cause of world peace and co-operation.

I earnestly trust that the message of the Buddha, whose anniversary we recently celebrated, will ever guide us, and the spirit of the Father of the Nation will continue to inspire us.

#### MOTION FOR ADJOURNMENT

##### FOOD SITUATION IN EASTERN U.P.

Mr. Speaker: I have received notice of an Adjournment Motion tabled by Shri S. L. Saksena. It says:

"That the House do adjourn to consider the failure of the Gov-

ernment to take adequate measures to meet to near-famine conditions prevailing in the various districts of Eastern U.P., particularly in Gorakhpur, Deoria and Basti districts, where the early paddy, late paddy and the Rabi crops have all failed owing to draught, floods, heavy and untimely rains and hailstorms repeatedly during the last three years, leading to utter destruction of the peasantry and resulting at the present day in mass starvation of the people".

How is this an urgent matter? It has been there for nearly three years.

Shri S. L. Saksena (Gorakhpur Distt.—North): It is now that the backbone of the peasantry has been broken, and the position is very bad in these days. In fact, during our election campaign, I found that people were starving for three, four and five days continuously, and nothing was done to relieve their suffering. I therefore think that something should be done. Unless adequate measures are taken to give employment and food to the people, there will be starvation in the very near future.

Mr. Speaker: Is the State Government not there? What has the hon. Minister to say?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): As you have rightly observed, the distribution of foodgrains is the responsibility of the State Government. So far as the Government of India are concerned, we are placing at the disposal of the State the quantities of foodgrains that it requires. I am not in possession of very accurate facts at the moment, but generally the facts are that the State Government has been taking large quantities; it has opened a large number of shops; foodgrains are being sold at subsidised rates, well within the buying capacity of the people. I am not aware of any mass starvation or anything of that kind. In fact, conditions, if anything, have improved lately on account of the approach of the Rabi